

# Soon, project to identify unknown polluting sources of river Ganga

**IN THE OFFING** This project will use geospatial technology to map the course of the river

**Suparna Roy**  
suparna.roy@htlive.com

**DEHRADUN:** In a bid to rejuvenate Ganga, Dehradun-based Survey of India along with Namami Gange is going to start a project where geospatial technology would be used to identify unknown sources of pollutants entering the river.

The announcement was made during an inaugural function in the capital city on Thursday. Yashpal Arya, transport minister of Uttarakhand, was the chief guest of the inaugural function.

SK Singh, project director National Mission for Clean Ganga (Survey of India) said, "Known sources of pollutants can be identified through information from civic bodies of different states through which the Ganga flows. But we want to identify the unknown polluting sources through mapping the river." The mapping would be done for the whole course starting from Rishikesh till Ganga Sagar. Area of mapping includes the entire corridor of Ganga, spanning across 45,000 sq km, covering five major states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar and West Bengal. A 10km of buffer on each bank would be included in the map.

In this project, GIS ready data



■ Lt Gen. Girish Kumar, Surveyor General of India, presents a memento to cabinet minister Yashpal Arya at a seminar on Ganga rejuvenation in Dehradun on Thursday. VINAY SANTOSH KUMAR/HT PHOTO

sets, including high resolution digital elevation model, would be created which would facilitate in Ganga River Basin Management, designing an efficient sewerage or waste management system and controlling pollution in river site areas. The project would be completed in 15 months from now, that is by October 2020.

Singh further said that the remote sensing technology of LiDAR and drones will be used

to map the buffer areas, identifying the coordinates of a particular area and digitally photographing it.

"After the digital mapping of a place is done, people will also be sent on ground for data validation. By merging the digital map and photographic evidence, we will come to know which are the sources which are not there in any of the government public drainage maps and then the authorities concerned

can act accordingly."

Lt Gen. Girish Kumar, Surveyor General of India, heading the event, said, "Ganga is not just a river but it is a symbol of faith for every citizen of the country. We have to protect this faith and for that the river needs to be kept clean. In this programme, we plan to rejuvenate the river, based on mapping, with focus on location, so that we can know the exact point where work needs to be done."



देहरादून। शुक्रवार • 28 जून • 2019

सहारा

# गंगा स्वच्छ अभियान के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

सर्वे आफ इंडिया गंगा को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने की परियोजनाओं में अहम योगदान दे रहा है। संस्थान ने इसके लिए डाटा बेस बनाया है। सर्वे आफ इंडिया ने गंगा और हुगली नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी चौड़े गलियारे के लिए हाई रेजोल्यूशन डिजिटल थ्री-डी माडल और जीआईएस डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस के जरिये गंगा स्वच्छता के परियोजनाएं सफल होंगी।

यह जानकारी जनरल आफ इंडिया ले. जनरल गिरीश कुमार ने हाथीबड़कला में आयोजित कार्यक्रम में दी। हाथीबड़कला स्थित बिग्रेडियर गंभीर सिंह आडिटोरियम में आयोजित 'जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कार्यशाला' में विशेषज्ञों ने राय दी। विभिन्न संस्थानों से आए विशेषज्ञों के साथ यूजर इंटरैक्शन मीट का आयोजन किया गया।

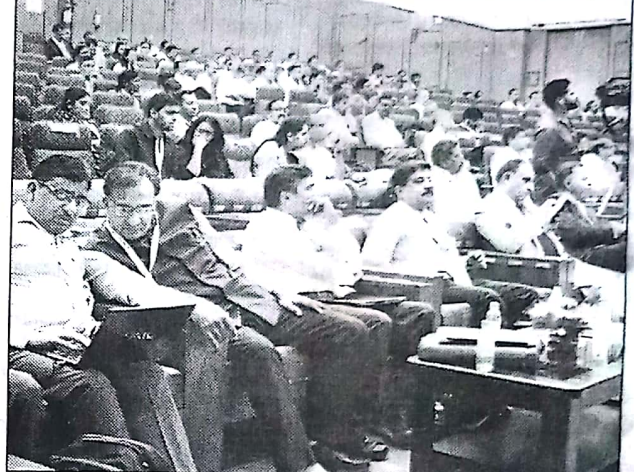


कार्यशाला में विचार व्यक्त करते विशेषज्ञ।

मीट में विभिन्न नोडल एजेंसियों और स्वच्छ गंगा मिशन के अन्य हितधारकों के बीच भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर कम हो रहे हैं। नदियों

की चौड़ाई कम हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिये होगा।

वह समय हमारे शहरों में दिखने लगा है। पानी को लेकर मारपीट होने लगी है। इसलिये हम लोगों को ठोस कार्य योजना बनानी होगी। कार्यशाला में एनएमसीजी के



कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य।

डीजी राजीव रंजन मिश्रा, आईआईआरएस के निदेशक डा. प्रकाश चौहान, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक प्रो. एमपीएस विष्ट ने हिमालयी इकोलाजी पर प्रस्तुतिकरण दिया। आईआईटी कानपुर के प्रो. भरत लोहानी ने लाइडर मैपिंग के फायदे

बताए। इस अवसर पर झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से डा. सर्वेश सिंहल, जीएंडआरबी के निदेशक डा. एसके सिंह, आरटीईएस, एनएमसीजी के उपाध्यक्ष पीयूष गुप्ता व वैज्ञानिक डा. मोहित कुमार पूनिया आदि मौजूद थे।



गंगा और हुगली के दोनों किनारों पर दस किमी क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन डिजी डाटा तैयार, सर्वे ऑफ इंडिया में हुई कार्यशाला

# गंगा स्वच्छता में सर्वे ऑफ इंडिया भी योगदान करेगा

## कार्यशाला

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

सर्वे ऑफ इंडिया गंगा को स्वच्छ बनाने की परियोजनाओं में अहम योगदान दे रहा है। स्वच्छ गंगा के लिए नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और सर्वे ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया है। इसके तहत सर्वे ऑफ इंडिया ने गंगा और हुगली नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी चौड़े गलियारे को हाई रेजोल्यूशन डिजिटल थ्री-डी मॉडल (डोईएम) और जीआईएस डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस के जरिये ही गंगा स्वच्छता की तमाम परियोजनाएं अंजाम तक पहुंचेंगी।

ये जानकारी सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ले. जनरल गिरीश कुमार ने हाथीबड़कला स्थित ब्रिगेडियर गंभीर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय 'जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कार्यशाला' में दी। विभिन्न संस्थानों से आये विशेषज्ञों के साथ यूजर इंटरैक्शन मीट का आयोजन भी किया गया।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि समाज



सर्वे आडिटोरियम में गुरुवार को नमामि गंगे पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए तैयार कलाकार। • हिन्दुस्तान

कल्याण मंत्री यशपाल आर्य रहे। उन्होंने कहा कि अक्सर सुनने में आता था जब विशेषज्ञ कहते थे कि आने वाले समय

में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिये होगा। लेकिन वह समय तो हमारे शहरों में अब दिखने लगा है। शहरों में पानी को लेकर

मारपीट होने लगी है। इसलिये ठोस कार्य योजनाएं बनानी होंगी। एनएमसीजी के डीजी राजीव रंजन मिश्रा,



मुख्य अतिथि यशपाल आर्य और मेयर सुनील उनियाल गंगा में दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया। • हिन्दुस्तान

आईआईआरएस के निदेशक डा. प्रकाश चौहान, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक प्रो. एमपीएस बिट ने हिमालयी इकोलॉजी पर प्रस्तुतीकरण दिया। आईआईटी कानपुर से प्रो. भरत लोहानी लाइडर मैपिंग के फायदे बताए। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से डा. सर्वेश सिंघल, जीएंडआरबी के निदेशक डा. एसके सिंह, आरटीईएस, एनएमसीजी के उपाध्यक्ष पियूष गुप्ता, वैज्ञानिक डा. मोहित कुमार पूनिया भी मौजूद रहे।



# गंगा, हुगली का तैयार होगा जीआईएस डाटा

नजर रखेगा सर्वे ऑफ इंडिया, भूस्थानिक तकनीक के जरिये गंगा की होगी मैपिंग

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने बताया कि गंगा और हुगली जैसी नदियों की सेहत पर सर्वे ऑफ इंडिया बारीकी से नजर रख रहा है। स्वच्छ गंगा के लिए नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के वैज्ञानिकों के साथ हाथ मिलाया गया है। इसके तहत गंगा और हुगली के दोनों किनारों पर 10 किमी चौड़े गलियारे के लिए हाई रेजोल्यूशन डिजिटल थ्रीडी मॉडल डीईएम और जीआईएस डाटाबेस तैयार किया गया है।

हाथीबड़कला स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित सेमिनार में महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय नदी को नया जीवन देने में सर्वे आफ इंडिया नमामि गंगे परियोजना को धरातल पर उतारने में योगदान देगा। गंगा में उन स्थानों को चिह्नित किया जाएगा जो इसकी स्वच्छता में बाधा बने हुए हैं। आईआईटी,



सेमिनार में संबोधित करते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य। अमर उजाला

## सर्वे आफ इंडिया में वैज्ञानिक सेमिनार, देश के कई संस्थानों ने दिए व्याख्यान

इसरो समेत अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सेमिनार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि गंगा की स्वच्छ और अविरल बनाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। लेकिन वैज्ञानिकों की भागीदारी अहम है। सेमिनार में इसरो, आईआईटी समेत देश के कई तकनीकी संस्थानों से पहुंचे विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए।

सेमिनार में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा, आईआईआरएस के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक प्रो. एमपीएस बिष्ट समेत कई वैज्ञानिकों ने हिमालय की पारिस्थितिकी पर प्रस्तुतिकरण दिया। कानपुर आईआईटी के प्रो. भरत लोहानी ने लाइडर मैपिंग के बारे में बताया। सेमिनार में डॉ. सर्वेश सिंघल, एमसीजी के उपाध्यक्ष पीयूष गुप्ता, वैज्ञानिक डॉ. मोहित कुमार आदि उपस्थित रहे।



# सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया गंगा का आधुनिक डाटाबेस

## सर्वे ऑफ इंडिया ने गंगा और हुगली नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी चौड़े गलियारे पर किया अध्ययन

जागरण संवाददाता, देहरादून : सर्वे ऑफ इंडिया जीवनदायिनी गंगा को स्वच्छ बनाने की परियोजना 'नमामि गंगे' में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गंगा की निर्मलता एवं स्वच्छता के लिए नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर काम करेंगे। जिसके तहत सर्वे ऑफ इंडिया ने गंगा और हुगली नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर चौड़े गलियारे के लिए हाई रेजोल्यूशन डिजिटल श्री-डी मॉडल (डीईएम) और जीआइएस डाटाबेस तैयार किया है। इस डाटाबेस के जरिये ही गंगा स्वच्छता की तमाम परियोजनाएं सफल हो पाएंगी।

यह जानकारी गुरुवार को सर्वे ऑफ इंडिया के ले. जनरल (वीएसएम) गिरीश कुमार ने हाथीबड़कला स्थित ब्रिगेडियर गंभीर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय 'जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी



सर्वे ऑडिटोरियम में 'गंगा पुनर्जीवन पर आयोजित कार्यशाला' को संबोधित करते मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य। साथ में मंचासीन विशिष्ट अतिथि महापौर सुनील उनियाल गामा व सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ले. जनरल गिरीश कुमार व अन्य।



गंगा पुनर्जीवन पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित वैज्ञानिक • जागरण

कार्यशाला' में दी। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों से आए विशेषज्ञों के साथ यूजर इंटरैक्शन मीट का आयोजन भी किया गया। जिसमें विभिन्न नोडल एजेंसियों और

स्वच्छ गंगा मिशन के अन्य हितधारकों के बीच भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के संबंध में चर्चा हुई। कार्यशाला में एनएमसीजी के डीजी राजीव रंजन मिश्रा, आइआइआरएस

के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक प्रो. एमपीएस बिष्ट ने हिमालयी इकोलॉजी पर प्रस्तुतिकरण दिया। जबकि आइआइटी

कानपुर से प्रोफेसर भरत लोहानी ने लाइवर मैपिंग के फायदे बताए। इस मौके पर झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से डॉ. सर्वेश सिंघल, जीएंडआरबी के निदेशक डॉ. एसके सिंह, आरटीईएस, एनएमसीजी के उपाध्यक्ष पियूष गुप्ता, वैज्ञानिक डॉ. मोहित कुमार पूनिया आदि मौजूद रहे। ग्लोबल वार्मिंग से घट रहे ग्लेशियर: नमामि गंगे के तहत आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य रहे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर कम हो रहे हैं, लिहजा नदियों की चौड़ाई भी कम हो रही है। विशेषज्ञ कहते थे कि आने वाले समय में तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा। लेकिन वह समय तो हमारे शहरों में आज ही दिखने लगा है। शहरों में लोगों में पानी को लेकर मारपीट होने लगी है।

हिन्दुस्तान

देहरादून • शुक्रवार • 28 जून 2019

# नदियों में बाढ़ की सूचना चार दिन पहले मिलेगी

हिन्दुस्तान

एक्सप्लूजिव

देहरादून | मनमीत

2024 के बाद गंगा नदी के साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों की तमाम नदियों की बाढ़ से होने वाले नुकसान से अब बचाया जा सकेगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय

## पूरे देश में जल्द लागू होगा प्रोजेक्ट: सिंह

सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ले. जनरल गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो रहा है, इसके बाद पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में दस केंद्रीय संस्थान और यूपी, बिहार और नार्थ ईस्ट के राज्यों के 39 संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।

की ओर से बनाया जा रहा 'नेशनल वॉटर इंफॉर्मेशन सिस्टम' चार दिन पहले ही संबंधित जिला प्रशासन को

सूचित कर देगा कि प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बाढ़ का कितना पानी आएगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में राहत और बचाव

के इंतजाम को वक्त मिल सकेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से वित्त पोषित नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत सर्वे ऑफ इंडिया को इस परियोजना का थ्रीडी सर्वे वर्ष 2020 तक मंत्रालय को सौंपना है। इसके बाद चार साल में यूपी, बिहार, उत्तरी पूर्वी राज्यों की नदियों के किनारे स्थित गांव-शहरों में उपकरण लगेंगे, जो बाढ़ की सटीक सूचनाएं देंगे।

➤ संबंधित खबर पेज 07